भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.07.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1081 का उत्तर

बिहार में रेल परियोजनाएं

1081. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:
श्री सुनील कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कार्यान्वयन हेतु घोषित नई रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) आरम्भ की गई नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और
(ग) उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिन्हें अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है और उक्त परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

बिहार में रेल परियोजनाओं के संबंध में 26.07.2023 को लोक सभा में श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी और श्री सुनील कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 1081 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाएं राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत की जाती है, क्योंकि भारतीय रेल नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020-21 से 2022-23 और चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से पड़ने वाली 18 किलोमीटर लंबाई की 313 करोड़ रू की लागत वाली 03 रेल परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है।

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4,950 किलोमीटर कुल लंबाई की 70,672 करोड़ रुपए की लागत वाली 54 रेल परियोजनाएं (32 नई लाइनें, 04 गेज परिवर्तन और 18 दोहरीकरण), योजना/अनुमोदन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,505 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2023 तक 25,702 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

किसी भी परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

बिहार राज्य में परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर), पूर्व रेलवे (ईआर), पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) जोन द्वारा कवर की जाती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजना-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board > About Indian Railways> Railway Board Directorates> Finance (Budget)> Pink Book(year)>Railways-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme (RSP) पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

वर्ष 2014 से, बजट आबंटन और पूरे भारतीय रेलवे में उसके अनुरूप परियोजनाओं की कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बिहार राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाले अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2014-19 के दौरान बढ़ाकर 3,061 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है,जो 2009-14 के दौरान 1,132 करोड़ रु. प्रति वर्ष के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 170% अधिक है। इन आबंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बढ़ाकर 4,093 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक

बजट आबंटन से 262% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4,489 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 297% अधिक), वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5,560 करोड़ रुपए (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 391% अधिक) और वित्त वर्ष 2022-23 में 6,606 करोड़ रुपए (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 484% अधिक) कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए,इन परियोजनाओं के लिए अभी तक का उच्चतम बजट परिव्यय 8,505 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है, जो 2009-2014 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय (1,132 करोड़ रुपए) से 651% अधिक है।

2014-23 के दौरान, बिहार राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से पड़ने वाले 1308 किलोमीटर (347 किमी नई लाइन,475 किमी आमान परिवर्तन और 486 किमी दोहरीकरण) खंड को 145.33 किलोमीटर प्रति वर्ष की औसत दर पर कमीशन किया गया है,जो 2009-14 के दौरान की गई कमिशनिंग (63.6 किलोमीटर/वर्ष) से 129% अधिक है।

****